

DAILY CURRENT AFFAIRS

IN HINDI

SPECIAL FOR UPSC & GPSC EXAMINATION

DATE : 30-12-25



UPSC CSE के लिए द हिंदू समाचार पत्र के महत्वपूर्ण समाचार लेख और संपादकीय

मंगलवार, 30 दिसंबर, 2025

संस्करण : अंतर्राष्ट्रीय विषय-सूची

पेज 01 पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन III: भारतीय अर्थव्यवस्था	विनिर्माण और पूंजीगत वस्तुओं की वृद्धि दर नवंबर में आईआईपी वृद्धि दर 25 महीने के उच्च स्तर 6.7 प्रतिशत पर पहुंच गई।
पेज 06 पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन III : विज्ञान और तकनीक / प्रारंभिक परीक्षा	डीएसी ने 79,000 करोड़ रुपये की रक्षा खरीद को मंजूरी दी।
पेज 08 पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन-II : शासन / प्रारंभिक परीक्षा	मॉडल आचरण: भारत को एआई संसाधनों तक पहुंच में सुधार करना चाहिए, और अपने कार्यबल को कुशल बनाना चाहिए
पेज 08 पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन-II : भारतीय राजनीति / प्रारंभिक परीक्षा	भारत के अगले विकास चरण के लिए शांत नींव
पेज 11 पाठ्यक्रम : सामान्य अध्ययन-ii & iii : अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भारतीय अर्थव्यवस्था	भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता क्या है?
पेज 08 : संपादकीय विश्लेषण पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन-I : भारतीय समाज और सामाजिक मुद्दे	एकतरफा तलाक के सभी रूपों को अमान्य करना

पेज 01 : सामान्य अध्ययन III : भारतीय अर्थव्यवस्था / प्रारंभिक परीक्षा

भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) ने नवंबर 2025 में 6.7% की 25 महीने की उच्च वृद्धि दर्ज की, जिसके कारण विनिर्माण (8%) और पूंजीगत सामान (10.4%) में मजबूत विस्तार हुआ। यह अक्टूबर में 0.5% की गिरावट से तेज पलटाव को दर्शाता है, जो बेमौसम बारिश और त्योहारी कैलेंडर प्रभावों के कारण हाल के व्यवधानों के बाद औद्योगिक गति में पुनरुद्धार का संकेत देता है।

Manufacturing, capital goods lead IIP growth to 25-month high of 6.7% in Nov.

The Hindu Bureau
NEW DELHI

The Index of Industrial Production (IIP) growth reached a 25-month high of 6.7% in November, driven by broad-based gains led by manufacturing and capital goods sectors, data released by the Union Statistics and Programme Implementation Ministry on Monday showed.

Within the IIP, the manufacturing output growth accelerated to a 25-month high of 8%. This was on a relatively high base of 5% in November 2024. "While the year-on-year IIP growth surged to a 25-month high of 6.7% in November 2025 from 0.5% in October 2025, this upsw-



ing largely reflects the shift in the festive calendar, restocking after the festive season sales, as well as some normalisation in activity across mining and electricity segments following the excess unseasonal rains in the previous month," Aditi Nayar, chief

economist, ICRA Ltd., said.

Ms. Nayar said that despite the demand boost following GST rate rationalisation in September, IIP growth averaged 3.6% during the October-November period, lower than the 4.3% expansion seen in the July-September quarter.

The infrastructure and construction sectors grew at 12.1% in November, the fastest since October 2023.

Buoyed by strong performances in manufacturing and construction sectors, the capital goods sector recorded an 11-month-high growth of 10.4% in November.

Mining output growth accelerated to a three-month high of 5.4% in November. The electricity sector was the only one to contract, declining by 1.5% in November, down from a growth of 4.4% in November last year.

Consumer durables and consumer non-durables sectors rebounded in November, growing 10.3% and 7.3%, respectively.

प्रमुख रुझान और क्षेत्रीय प्रदर्शन

विकास इंजन के रूप में विनिर्माण

- विनिर्माण वृद्धि 8% तक बढ़ गई, जो नवंबर 2024 में 5% के अपेक्षाकृत उच्च आधार के बावजूद दो वर्षों में सबसे अधिक है।
- यह न केवल एक आधार प्रभाव का सुझाव देता है, बल्कि उत्पादन गतिविधि में एक वास्तविक सुधार का सुझाव देता है, जो उत्सव के बाद की रीस्टॉकिंग और आपूर्ति श्रृंखलाओं के स्थिरीकरण से सहायता प्राप्त करता है।

पूंजीगत वस्तुएं: निवेश पुनरुद्धार का संकेतक

- पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन 10.4% (11 महीने का उच्चतम) बढ़ा।

- यह निजी और सार्वजनिक निवेश का एक प्रमुख संकेतक है, जो बेहतर व्यावसायिक विश्वास, बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और उच्च क्षमता निर्माण का संकेत देता है - जो मध्यम अवधि के विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

बुनियादी ढांचे और निर्माण को बढ़ावा

- बुनियादी ढांचे और निर्माण वस्तुओं में 12.1% की वृद्धि हुई, जो अक्टूबर 2023 के बाद से सबसे तेज है।
- यह विशेष रूप से सड़कों, रेलवे, आवास और शहरी बुनियादी ढांचे में निरंतर सरकारी पूंजीगत व्यय को दर्शाता है।

खनन और बिजली: अलग-अलग रुझान

- खनन उत्पादन में 5.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो तीन महीने का उच्च स्तर है, जो मौसम संबंधी व्यवधानों के बाद सामान्य होने का संकेत देता है।
- बिजली में 1.5 प्रतिशत की कमी आई है, जो असमान मांग वसूली और संभावित दक्षता लाभ या क्षेत्र-विशिष्ट बाधाओं का सुझाव देती है।

उपभोक्ता मांग पुनरुद्धार

- कंज्यूमर ड्यूरेबल्स (10.3%) और नॉन-ड्यूरेबल्स (7.3%) ने रिबाउंड किया, जो बेहतर विवेकाधीन और आवश्यक खपत की ओर इशारा करता है।
- शहरी मांग में नरमी पर हाल की चिंताओं को देखते हुए यह महत्वपूर्ण है।

अंतर्निहित ड्राइवर

- त्योहारी कैलेंडर प्रभाव: त्योहारों के स्थानांतरण के कारण नवंबर में मांग बढ़ गई।
- रीस्टॉकिंग चक्र: उत्सव के बाद इन्वेंट्री पुनर्निर्माण ने विनिर्माण उत्पादन का समर्थन किया।
- सामान्य अध्ययन टी दर युक्तिकरण (सितंबर): मांग में वृद्धि होने पर, हालांकि इसका प्रभाव मध्यम दिखाई देता है।
- मौसम सामान्यीकरण: अक्टूबर में अधिक बारिश के कारण व्यवधान के बाद खनन और बिजली ठीक हो गई।

महत्वपूर्ण मूल्यांकन

- अभी तक व्यापक आधार पर निरंतर वृद्धि नहीं हुई है: नवंबर की वृद्धि के बावजूद, अक्टूबर-नवंबर के लिए औसत आईआईपी वृद्धि 3.6% थी, जो दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में 4.3% से कम थी। इससे पता चलता है कि रिकवरी असमान और प्रासंगिक है, अभी तक मजबूत नहीं हुई है।
- निवेश बनाम उपभोग संतुलन: मजबूत पूंजीगत वस्तुओं का प्रदर्शन उत्साहजनक है, लेकिन निरंतर औद्योगिक विकास के लिए टिकाऊ खपत पुनरुद्धार की आवश्यकता होती है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में।
- लाल झंडे के रूप में बिजली संकुचन: बिजली उत्पादन में लगातार कमजोरी औद्योगिक मापनीयता को बाधित कर सकती है यदि मांग आपूर्ति की तैयारी से तेज होती है।

व्यापक व्यापक आर्थिक विषयों के साथ संबंध

- आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया: विनिर्माण पुनरुद्धार दीर्घकालिक औद्योगिक नीति लक्ष्यों के अनुरूप है।
- कैपेक्स के नेतृत्व वाली विकास रणनीति: निजी निवेश में सार्वजनिक निवेश की भीड़ पर सरकार के जोर को पुष्ट करता है।

- रोजगार क्षमता: विनिर्माण और निर्माण विकास रोजगार सृजन का समर्थन कर सकता है, जो समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
- मुद्रास्फीति-विकास व्यापार-बंद: आपूर्ति बाधाओं के बिना औद्योगिक विस्तार लागत-धक्का मुद्रास्फीति को प्रबंधित करने में मदद कर सकता है।

निष्कर्ष

नवंबर 2025 IIP डेटा भारत की औद्योगिक गतिविधि में एक चक्रीय वृद्धि का संकेत देता है, जिसमें विनिर्माण और पूंजीगत सामान एक मजबूत जोर प्रदान करते हैं। जबकि हेडलाइन संख्या अनुकूल आधार प्रभावों और उत्सव से संबंधित कारकों को दर्शाती है, मजबूत पूंजीगत सामान और बुनियादी ढांचे की वृद्धि निवेश चक्र के क्रमिक पुनरुद्धार की ओर इशारा करती है। हालांकि, इस गति को निरंतर, व्यापक-आधारित औद्योगिक विकास, निरंतर मांग पुनरुद्धार, ऊर्जा क्षेत्र की स्थिरता और निरंतर नीतिगत समर्थन में बदलने के लिए आवश्यक होगा।

UPSC प्रारम्भिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. आईआईपी में पूंजीगत वस्तुओं की वृद्धि को आमतौर पर अर्थव्यवस्था में निजी निवेश के रुझानों के लिए एक प्रॉक्सी माना जाता है।
2. बिजली उत्पादन में संकुचन का तात्पर्य समग्र औद्योगिक उत्पादन में संकुचन से है।
3. आईआईपी के तीन प्रमुख क्षेत्रों में विनिर्माण का वजन सबसे अधिक है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 3
- (b) केवल 1
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

UPSC मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: मूल्यांकन करें कि त्योहारी मांग और **GST** युक्तिकरण जैसे अल्पकालिक कारक मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे दीर्घकालिक औद्योगिक नीति उद्देश्यों के साथ कैसे बातचीत करते हैं।

पेज 06 : सामान्य अध्ययन III : विज्ञान और तकनीक / प्रारंभिक परीक्षा

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने सेना, नौसेना और वायु सेना के लिए 79,000 करोड़ रुपये के रक्षा पूंजी अधिग्रहण के लिए आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) को मंजूरी दी है। यह अनुमोदन भारत के उभरते खतरे के माहौल, सेवाओं के बीच संयुक्तता पर जोर देने और आत्मनिर्भर भारत के तहत एक आत्मनिर्भर रक्षा औद्योगिक आधार के निर्माण के व्यापक उद्देश्य के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।

DAC gives its nod for defence purchases worth ₹79,000 cr.

Committee accorded approval for the Army's proposal for radars and guided rocket ammunition, Navy's request for tugs and high frequency radio, and Air Force's proposal for missiles, simulators

The Hindu Bureau
NEW DELHI

The Defence Acquisition Council (DAC), chaired by Defence Minister Rajnath Singh, on Monday accorded Acceptance of Necessity (AoN) for capital acquisition proposals amounting to about ₹79,000 crore from the Army, Navy, and Air Force.

According to the Ministry of Defence, the DAC approved the procurement of Loiter Munition Systems for Artillery Regiments, Low Level Light Weight Radars, Long Range Guided Rocket Ammunition for the Pinaka Multiple Launch Rocket System (MRLS), and Integrated Drone Detection and Interdiction System (IDD&IS) Mk-II for the Indian Army.

The Loiter Munition Systems will enable precision strikes against tactical targets, while the Low Level Light Weight Radars will enhance detection and tracking of small, low-flying unmanned aerial systems. The Long Range Guided Rockets will significantly improve the range and accuracy of the Pinaka MRLS, enabling effective engagement of high-value targets.



Joint synergy: The ₹79,000-crore package is aimed at boosting the operational capabilities of the three Services. FILE PHOTO

The IDD&IS Mk-II, with enhanced range, will strengthen the protection of vital assets in tactical battle areas and the hinterland, the Defence Ministry said.

For the Indian Navy, the AoN was accorded for the procurement of Bollard Pull (BP) Tugs, High Frequency Software Defined Radio (HF SDR) Manpack systems, and the leasing of High Altitude Long Endurance (HALE) Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS).

The BP Tugs will assist naval ships and submarines during berthing, unberthing and manoeuvring in confined harbour wa-

ters. The HF SDR Manpack will enhance long-range secure communications during boarding and landing operations, while the HALE RPAS will provide persistent intelligence, surveillance and reconnaissance, and strengthen maritime domain awareness across the Indian Ocean Region.

For the Indian Air Force, the DAC approved the AoN for procurement of the Automatic Take-off and Landing Recording System, Astra Mk-II beyond-visual-range air-to-air missiles, Full Mission Simulators, and SPICE-1000 long-range guidance

DRDO tests Pinaka rocket

NEW DELHI

The Defence Research and Development Organisation (DRDO) on Monday successfully conducted the maiden flight test of the Pinaka Long Range Guided Rocket (LRGR-120) at the Integrated Test Range (ITR), Chandipur.

The Defence Ministry said that the test marked a major milestone in India's indigenous rocket artillery programme.

The Automatic Take-off and Landing Recording System will enhance aerospace safety by enabling high-definition, all-weather automatic recording of take-off and landing phases. Astra Mk-II missiles, with enhanced range, will boost the capability of IAF fighter aircraft to engage adversary targets from extended distances.

The Full Mission Simulator for the Light Combat Aircraft Tejas will strengthen pilot training in a cost-effective and safe environment, while SPICE-1000 kits will enhance the IAF's long-range precision strike capability.

रक्षा खरीद में एओएन का क्या अर्थ है?

एओएन भारत की रक्षा खरीद प्रक्रिया में पहला औपचारिक अनुमोदन चरण है। यह स्थापित करता है:

- उपकरण की परिचालन आवश्यकता,
- व्यापक लागत लिफाफा, और
- खरीद श्रेणी (भारतीय खरीदें, खरीदें और भारतीय बनाएं, पट्टे, आदि)।
- इस प्रकार, एओएन तत्काल अनुबंध को अंतिम रूप देने के बजाय रणनीतिक इरादे को दर्शाता है, लेकिन यह भविष्य की क्षमता विकास का एक महत्वपूर्ण संकेत है।

सेवा-वार विश्लेषण और रणनीतिक महत्व

1. भारतीय सेना: सटीकता, ड्रोन और काउंटर-यूएस पर ध्यान केंद्रित करें

प्रमुख अनुमोदनों में शामिल हैं:

- लोइटर म्यूनिशन सिस्टम: सामरिक लक्ष्यों के खिलाफ सटीक हमले सक्षम करें, जो हाल के संघर्षों (यूक्रेन, नागोर्नो-काराबाख) से सबक को दर्शाता है, जहां घूमने वाले हथियारों ने युद्ध के मैदान की गतिशीलता को बदल दिया।
- निम्न स्तर के हल्के वजन वाले रडार: सीमाओं के साथ असममित खतरों को संबोधित करते हुए, छोटे, कम उड़ान वाले ड्रोन का पता लगाना बढ़ाएं।
- पिनाका एमएलआरएस के लिए लंबी दूरी का गाइडेड रॉकेट गोला बारूद: रेंज और सटीकता में सुधार करता है, जिससे भारत की स्टैंड-ऑफ स्ट्राइक क्षमता बढ़ जाती है।
- इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम (IDD&IS) Mk-II: ड्रोन-आधारित हमलों के खिलाफ महत्वपूर्ण सैन्य और नागरिक संपत्तियों की सुरक्षा को मजबूत करता है।

2. भारतीय नौसेना: समुद्री डोमेन जागरूकता और आईओआर फोकस

स्वीकृतियों में शामिल हैं:

- बोलाड पुल (बीपी) टग: सुरक्षित बंदरगाह संचालन के लिए आवश्यक, अक्सर अनदेखा किया जाता है लेकिन नौसेना की तत्परता के लिए महत्वपूर्ण है।
- एचएफ सॉफ्टवेयर डिफाईंड रेडियो (एसडीआर) मैनपैक: सुरक्षित, लंबी दूरी के संचार में सुधार करता है, खासकर बोर्डिंग और उभयचर संचालन के दौरान।
- हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंज्योरेंस (HALE) RPAS को पट्टे पर देना: हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में लगातार खुफिया, निगरानी और टोही (ISR) को सक्षम बनाता है।

3. भारतीय वायु सेना: वायु श्रेष्ठता, प्रशिक्षण और सटीक हड़ताल

स्वीकृत प्रणालियों में शामिल हैं:

- एस्ट्रा एमके-II बियाँड विजुअल रेंज (बीवीआर) मिसाइल: हवा से हवा में मार करने की क्षमता को बढ़ाता है और आयात पर निर्भरता कम करता है।
- SPICE-1000 मार्गदर्शन किट: उच्च सटीकता के साथ लंबी दूरी के सटीक स्ट्राइक विकल्पों को मजबूत करें।
- स्वचालित टेक-ऑफ और लैंडिंग रिकॉर्डिंग सिस्टम: एयरोस्पेस सुरक्षा और दुर्घटना जांच में सुधार करता है।
- एलसीए तेजस के लिए पूर्ण मिशन सिमुलेटर: लागत प्रभावी और जोखिम मुक्त वातावरण में पायलट प्रशिक्षण को बढ़ावा देता है।

व्यापक रणनीतिक और नीतिगत निहितार्थ

संयुक्तता और एकीकृत क्षमता विकास

- यह पैकेज सेवा-विशिष्ट साइलो से आगे बढ़ते हुए त्रि-सेवा तालमेल को दर्शाता है।
- थिएटर कमांड के तहत भविष्य के एकीकरण का समर्थन करता है।

रक्षा में आत्मनिर्भर भारत

- कई प्रणालियां (पिनाका, अस्त्र, आईडीडी एंड आईएस) स्वदेशी रूप से विकसित या निर्मित हैं, जो घरेलू रक्षा उद्योग और एमएसएमई को बढ़ावा देती हैं।

मात्रा से गुणवत्ता में बदलाव

- सटीकता, आईएसआर, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और ड्रोन पर ध्यान केंद्रित करना केवल संख्यात्मक विस्तार के बजाय गुणात्मक परिवर्तन का संकेत देता है।

समकालीन संघर्षों से सबक

- काउंटर-ड्रोन सिस्टम, लोडटर म्यूनिशन और आईएसआर प्लेटफॉर्म आधुनिक, प्रौद्योगिकी-गहन युद्ध से भारत की सीख को दर्शाते हैं।

निष्कर्ष

डीएसी द्वारा 79,000 करोड़ रुपये के रक्षा अधिग्रहण की मंजूरी नियमित खरीद से अधिक का प्रतिनिधित्व करती है – यह प्रौद्योगिकी-संचालित, सटीक-केंद्रित और संयुक्त सैन्य क्षमताओं के प्रति भारत के रणनीतिक पुनर्मूल्यांकन को दर्शाती है। काउंटर-ड्रोन सिस्टम, लंबी दूरी के सटीक हथियारों, आईएसआर परिसंपत्तियों और उन्नत प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता देकर, भारत स्वदेशी रक्षा निर्माण को मजबूत करते हुए अपने सशस्त्र बलों को भविष्य के युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। UPSC के लिए, यह विकास राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा सुधारों, स्वदेशीकरण और भू-राजनीतिक अनिवार्यताओं के बीच संबंध का एक पाठ्यपुस्तक उदाहरण है।

UPSC प्रारम्भिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न : रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसकी अध्यक्षता भारत के रक्षा मंत्री द्वारा की जाती है।
2. आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) रक्षा खरीद का अंतिम चरण है।
3. डीएसी ने सशस्त्र बलों के लिए पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 3
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

पेज 08 : सामान्य अध्ययन II : शासन / प्रारंभिक परीक्षा

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) शासन एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक नीति चुनौती के रूप में उभरा है क्योंकि एआई सिस्टम तेजी से आर्थिक निर्णय लेने, सामाजिक व्यवहार और मनोवैज्ञानिक कल्याण को प्रभावित कर रहा है। भारत का वर्तमान नियामक दृष्टिकोण काफी हद तक एक समर्पित एआई सुरक्षा या उपभोक्ता संरक्षण व्यवस्था के बजाय मौजूदा कानूनी ढांचे-आईटी अधिनियम और नियमों, क्षेत्रीय वित्तीय नियमों और डेटा संरक्षण मानदंडों पर निर्भर करता है।

इसके विपरीत, चीन जैसे देशों ने स्पष्ट "देखभाल के कर्तव्य" ढांचे के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया है, विशेष रूप से मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक नुकसान को संबोधित करने के लिए। इसलिए, बहस केवल इस बारे में नहीं है कि एआई को कैसे विनियमित किया जाए, बल्कि यह भी है कि भारत की सीमित घरेलू एआई क्षमता को देखते हुए, मूल्य श्रृंखला विनियमन के कब और किस स्तर पर हस्तक्षेप करना चाहिए।

भारत की वर्तमान नियामक स्थिति: ताकत और अंतराल

1. खंडित लेकिन कार्यात्मक विनियमन

भारत वर्तमान में अप्रत्यक्ष रूप से AI को नियंत्रित करता है:

- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) डीपफेक, ऑनलाइन धोखाधड़ी और सिंथेटिक सामग्री लेबलिंग जैसे जोखिमों को दूर करने के लिए IT नियमों का उपयोग करता है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वित्त में जिम्मेदार AI उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ऋण में मॉडल जोखिम प्रबंधन और FREE-AI ढांचे के लिए अपेक्षाएं पेश की हैं।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने विनियमित संस्थाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले एआई उपकरणों में जवाबदेही और व्याख्या पर जोर दिया है।

ताकत:

यह दृष्टिकोण प्रारंभिक चरण में अति-विनियमन से बचता है और विशेष रूप से वित्त में क्षेत्रीय विशेषज्ञता का लाभ उठाता है।

सीमा:

भारत में एक स्पष्ट AI उपभोक्ता सुरक्षा या उत्पाद देयता व्यवस्था का अभाव है, विशेष रूप से मनोवैज्ञानिक नुकसान, हेरफेर और भावनात्मक निर्भरता को संबोधित करना - ऐसे जोखिम जो पूरी तरह से गैरकानूनी-सामग्री-आधारित विनियमन द्वारा कवर नहीं किए गए हैं।

Model conduct

India must improve access to AI resources, and upskill its workforce

India has been regulating Artificial Intelligence (AI) use by expecting due diligence from platforms under the IT Act and Rules, regulating the financial sector, and with privacy and data protection Rules. It does not yet have a consumer safety regime that deals with the state's duty of care. China pitched such a regime with draft rules that it unveiled last week, which target emotionally interactive services, and propose to require companies to warn against excessive use and intervene when they detect signs of extreme emotional states. If these rules seem justified for targeting psychological dependence that general rules about unlawful content do not address, they may also be harsh because expecting providers to identify users' states can incentivise more intimate monitoring. India's posture is less intrusive, but also more incomplete, because it banks on existing laws. Thus, it regulates adjacent risks but has not articulated a duty of care *vis-à-vis* AI product safety, especially for psychological harms. MeitY has used the IT Rules to push platforms to curb deepfakes and fraud, and define and label "synthetically generated" content. Financial regulators have also adopted structural measures, with the RBI setting expectations to govern model risk in credit and developing its FREE-AI framework process and SEBI pushing for clear accountability on how regulated entities use AI tools. While some measures are preemptive, MeitY has been largely reactive.

India has a large ecosystem that adopts models but is far behind the U.S. and China in building frontier models of its own. In this context, it should beware the cons of 'regulate first, build later', especially since domestic capacity is lacking. A more practical way might be to consider how it can nurture a frontier model and govern the overall use of models, many of which will remain privately built and foreign for a while, inside Indian markets. On the first count, India can focus on improving access to computational resources, upskilling the workforce, increasing public procurement, and translating research to industry while sidestepping the pitfall of paralysis by consensus, which could increase dependency. On the second, India should consider regulating downstream use more assertively without choking upstream capability. It can do this by adding obligations on companies that are deploying products in high-risk contexts, and regulating how they monitor and respond to a model's behaviour, to existing privacy and consumer protection rules, for example, by expecting companies to submit incident reports, rather than requiring them to monitor users' emotions. This way, India can write rules for how Indians use models without assuming that the global technology trajectory will rearrange itself to match its preferences.

तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य: चीन बनाम भारत

भावनात्मक रूप से इंटरैक्टिव एआई सेवाओं पर चीन के मसौदा नियम पेश करते हैं:

- अत्यधिक उपयोग के खिलाफ अनिवार्य चेतावनी
- उपयोगकर्ताओं द्वारा भावनात्मक संकट के लक्षण दिखाने पर कंपनियों पर हस्तक्षेप करने की बाध्यता

निहितार्थ:

- ये नियम मनोवैज्ञानिक निर्भरता को एक नियामक चिंता के रूप में स्वीकार करते हैं।
- हालांकि, वे अति-दखल देने वाली निगरानी का जोखिम उठाते हैं, उपयोगकर्ताओं की भावनाओं की गहराई से निगरानी करने के लिए प्लेटफॉर्मों को प्रोत्साहित करते हैं, गोपनीयता और नागरिक स्वतंत्रता की चिंताओं को बढ़ाते हैं।
- भारत का दृष्टिकोण कम दखल देने वाला है, लेकिन कम व्यापक भी है, क्योंकि यह मानता है कि मौजूदा कानून पर्याप्त हैं और जिम्मेदारी का बोझ बड़े पैमाने पर प्लेटफॉर्मों के उचित परिश्रम पर डालता है, न कि स्पष्ट रूप से स्पष्ट रूप से स्पष्ट रूप से राज्य की देखभाल के कर्तव्य पर।

संरचनात्मक चुनौती: निर्माण के बिना विनियमन

- एक केंद्रीय चिंता पर प्रकाश डाला गया है कि अग्रणी एआई मॉडल विकास में भारत की कमजोर स्थिति है:
- भारत एक बड़ा अपनाने वाला और बाजार है, लेकिन अमेरिका और चीन के विपरीत, विदेशी निर्मित, निजी स्वामित्व वाले मॉडल पर निर्भर है।
- समय से पहले या भारी-भरकम विनियमन जोखिम "पहले विनियमित करें, बाद में बनाएं" जाल बनाते हैं, जिससे दीर्घकालिक तकनीकी निर्भरता बढ़ती है।

आगे की राह: एक संतुलित और संदर्भ-विशिष्ट रणनीति

1. घरेलू क्षमता का निर्माण (आपूर्ति-पक्ष फोकस)

भारत को प्राथमिकता देनी चाहिए:

- कम्प्यूटेशनल संसाधनों तक पहुंच (सार्वजनिक गणना बुनियादी ढांचा, क्लाउड क्रेडिट)।
- एआई अनुसंधान, तैनाती और सुरक्षा इंजीनियरिंग में कार्यबल का कौशल बढ़ाना।
- मांग पैदा करने और सीखने के प्रभाव पैदा करने के लिए एआई समाधानों की सार्वजनिक खरीद।
- उद्योग में अनुसंधान का अनुवाद, "आम सहमति से पक्षाघात" से बचना जो निष्पादन में देरी करता है।
- यह आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल संप्रभुता के व्यापक लक्ष्यों के अनुरूप है।

2. डाउनस्ट्रीम उपयोग को विनियमित करना, अपस्ट्रीम नवाचार को नहीं

उपयोगकर्ताओं की दखल देने वाली निगरानी के बजाय:

- उच्च जोखिम वाले संदर्भों (वित्त, स्वास्थ्य देखभाल, चुनाव, शिक्षा) में एआई परिनियोजन पर उच्च दायित्व लागू करें।
- घटना रिपोर्टिंग, ऑडिट ट्रेल्स और मॉडल व्यवहार की तैनाती के बाद की निगरानी की आवश्यकता होती है।
- इन दायित्वों को उपभोक्ता संरक्षण और गोपनीयता ढांचे में एकीकृत करें, जिससे एक कठोर एआई-विशिष्ट कोड बनाने के बजाय मौजूदा कानूनों का विस्तार किया जा सके।

- यह दृष्टिकोण भारत को यह नियंत्रित करने की अनुमति देता है कि भारतीय समाज में एआई का उपयोग कैसे किया जाता है, इसके नियंत्रण से परे वैश्विक प्रौद्योगिकी प्रक्षेपवक्र को फिर से आकार देने का प्रयास किए बिना।

व्यापक शासन महत्व

- उभरती प्रौद्योगिकियों में नवाचार और विनियमन के बीच तनाव को दर्शाता है।
- व्यवहार और मनोवैज्ञानिक नुकसान को संबोधित करने में सामग्री-केंद्रित विनियमन की सीमाओं पर प्रकाश डालता है।
- प्रौद्योगिकी शासन में राज्य की क्षमता, रणनीतिक स्वायत्तता और नियामक अनुक्रमण पर सवाल उठाता है।
- यह निर्देशात्मक नियंत्रणों की तुलना में अनुकूली, सिद्धांत-आधारित विनियमन के लिए भारत की प्राथमिकता को दर्शाता है।

निष्कर्ष

भारत का एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क वर्तमान में व्यावहारिक है लेकिन अधूरा है। जबकि मौजूदा कानूनों पर इसकी निर्भरता दखल देने वाली निगरानी से बचती है और नवाचार स्थान को संरक्षित करती है, यह एआई-प्रेरित उपभोक्ता और मनोवैज्ञानिक नुकसान के लिए देखभाल के स्पष्ट कर्तव्य को स्पष्ट करने में विफल है।

इष्टतम मार्ग न तो चीन-शैली के अतिक्रमण में है और न ही नियामक अतिसूक्ष्मवाद में, बल्कि एक अनुक्रमित रणनीति में है - पहले गणना पहुंच और कौशल के माध्यम से घरेलू एआई क्षमता का निर्माण, और साथ ही जवाबदेही और घटना-आधारित निरीक्षण के माध्यम से डाउनस्ट्रीम, उच्च जोखिम वाले उपयोगों को दृढ़ता से विनियमित करना। इस तरह के दृष्टिकोण से भारत को नागरिकों की सुरक्षा करने, निर्भरता कम करने और वैश्विक तकनीकी वास्तविकताओं के साथ तालमेल बिठाने में मदद मिलेगी।

UPSC प्रारम्भिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा एआई शासन के संदर्भ में "पहले विनियमन, बाद में निर्माण करें" शब्द की सबसे अच्छी व्याख्या करता है?

- (a) नवाचार पर उपभोक्ता संरक्षण को प्राथमिकता देना
- (b) घरेलू प्रौद्योगिकीय क्षमता विकसित होने से पहले कृत्रिम प्रौद्योगिकी विनियमन लागू करना
- (c) नैतिक मानकों को अंतिम रूप दिए जाने तक AI को अपनाने में देरी करना
- (d) स्वदेशी स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए विदेशी AI मॉडल को प्रतिबंधित करना

उत्तर : b)

UPSC मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे जोखिम पैदा करता है जो गैरकानूनी सामग्री से परे जाते हैं, जिसमें व्यवहार और मनोवैज्ञानिक नुकसान शामिल हैं। इस संदर्भ में, भारत में एआई शासन के लिए 'देखभाल के कर्तव्य' ढांचे की प्रासंगिकता पर चर्चा करें।

पेज 08 : सामान्य अध्ययन II : भारतीय राजनीति / प्रारंभिक परीक्षा

लेख में बताया गया है कि कैसे 2025 में भारत के विकास पथ को सुर्खियां बटोरने वाली घोषणाओं से कम और वृद्धिशील, संरचनात्मक सुधारों द्वारा अधिक आकार दिया गया है। जैसा कि भारत ने \$ 4 ट्रिलियन जीडीपी का आंकड़ा पार कर लिया है और अपने संप्रभु ऋण दृष्टिकोण में सुधार किया है, इसलिए अल्पकालिक विकास आवेगों से दीर्घकालिक संस्थागत क्षमता निर्माण पर जोर दिया गया है।

The quiet foundations for India's next growth phase

As 2025 draws to a close, the loud headlines are easy to spot, but what is easier to miss is the quieter work of governance, the steady, week after week clearing of bottlenecks – the cumulative push is what I mean by Reform Express 2025.

India crossed about \$4.1 trillion in nominal GDP and overtook Japan as the world's fourth largest economy. Standard and Poor's upgraded India's sovereign rating to BBB after 18 years, signalling that the macro story has acquired durability, not just speed. In an uncertain world where political churn has become the norm, India's stable leadership makes reforms credible, and credible reforms convert private caution into private investment.

I have seen, across negotiating tables, from the GATT and WTO system to multilateral forums, that rules are only as good as the incentives they create. When procedures are opaque, discretion expands, and then even well-intentioned policy ends up discouraging enterprise. When procedures are clean and time-bound, competition thrives, investment plans get executed, and jobs follow.

India's total exports hit \$825.25 billion during 2024-25, representing an annual growth of over 6%. To support this volume of trade, the government introduced several digital tools such as The Trade Connect ePlatform, a single digital window for exporters, and the Trade Intelligence and Analytics (TIA) portal for providing real-time market data.

The trade agreements

The India-United Kingdom Comprehensive Economic and Trade Agreement signed in July 2025 created a stronger platform for Indian exporters, with wide duty-free access and clearer pathways for services and skilled mobility. In December 2025, India signed a Comprehensive Economic Partnership Agreement with Oman, strengthening a strategic economic corridor for goods, services, and investment. India also concluded negotiations for a free trade agreement with New Zealand, expanding India's reach into high value markets and setting a template for disciplined, commercially meaningful agreements.

India's startup sector expanded to include over two lakh government-recognised startups, which helped create more than 21 lakh jobs. The Open Network for Digital Commerce (ONDC) processed over 326 million orders, averaging more than 5.9 lakh daily transactions. Additionally, the Government e-Marketplace (GeM) saw its cumulative transaction value cross ₹16.41 lakh crore, with 11 lakh micro and small enterprises receiving orders worth over ₹7.35 lakh crore.

India also improved its position in the Global Innovation Index, rising to 38th place among 139



Hardeep S. Puri

is Union Minister for Petroleum and Natural Gas, Government of India

economies. Efforts to simplify business operations resulted in the reduction of over 47,000 compliances and the decriminalisation of 4,458 legal provisions. By late November, the National Single Window System processed more than 8.29 lakh approvals. Infrastructure planning also saw changes as the PM GatiShakti National Master Plan opened to the private sector, and the Project Monitoring Group portal has onboarded over 3,000 projects valued at more than ₹76 lakh crore.

Better legislation

Embracing trust-based governance, Parliament passed the Repealing and Amending Bill 2025, clearing out 71 obsolete Acts that had outlived their purpose. Ease of doing business also moved closer to the entrepreneur through district-level reform frameworks, including the District Business Reform Action Plan 2025, which seeks to make local administrations more responsive, predictable, and accountable.

A modern labour regime matters for scale, for manufacturing, and for a services economy that wants to formalise jobs while expanding social security coverage. With the four labour codes coming into effect from November 21, 2025, 29 central labour laws have been consolidated into a simpler framework covering wages, industrial relations, social security and workplace safety.

The Securities Markets Code Bill was introduced to modernise securities law and strengthen the Securities and Exchange Board of India's investigative and enforcement capacity, with proposals for specialised market courts, stronger information sharing with regulators, and time-bound grievance redress. At a moment when retail participation has expanded and India is drawing larger global portfolio interest, regulatory clarity becomes part of national competitiveness, helping savings flow into productive investment.

Logistics is where reform becomes visible in costs, and 2025 saw a push to modernise the maritime backbone of trade. Nearly 95% of India's trade by volume and about 70% by value moves through maritime routes, so port and shipping efficiency is a competitiveness issue. The Indian Ports Act, 2025 replaced a colonial-era framework and introduced modern governance tools, including state-level dispute resolution, a statutory coordination council, and stronger norms on safety, disaster readiness and environmental preparedness. The Merchant Shipping Act, 2025 and the Carriage of Goods by Sea Act, 2025 further modernised shipping law, updating rules, liabilities and dispute frameworks to reflect contemporary commerce.

The Cabinet approved a package of ₹69,725 crore to strengthen shipbuilding, including a Maritime Development Fund of ₹25,000 crore

and components for financial assistance and development, points to a larger ambition: build industrial depth, reduce dependence, and keep freight value within India over time. This is industrial policy in the classic sense, creating an ecosystem where private capital can enter with a clearer risk framework, and where jobs are created not only in ports but across shipyards, components, engineering, and services.

A focus on energy

Energy reforms, too, were designed for long cycle investment. The Oilfields (Regulation and Development) Amendment Act, 2025 and the new Petroleum and Natural Gas Rules 2025 sought to reduce investor risk by emphasising stability of terms during the life of a lease, moving toward a single petroleum lease across the project life cycle, and putting clearer timelines on approvals. The Open Acreage Licensing Policy continued widening the exploration map, with Round X offering 25 blocks across about 0.2 million square kilometres, predominantly offshore, including deepwater and ultra deepwater opportunities. Alongside this, the National Deep Water Exploration Mission signalled a strategic focus on domestic resources, technology, and capability in complex exploration.

Reform Express 2025 also carried a strategic energy and technology dimension. Budget 2025 set out a Nuclear Energy Mission with an outlay of ₹20,000 crore to accelerate small modular reactors and other advanced designs, aligned with the national objective of reaching 100 GW of nuclear capacity by 2047, and a target of five indigenously designed operational small modular reactors by 2033. The Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India (SHANTI) Bill is a huge leap for modernising India's civil nuclear framework and opening a pathway for carefully regulated private participation. Nuclear energy adds firm, low carbon power to the grid, and strengthens India's ability to build advanced manufacturing, data infrastructure, and energy intensive industry with greater confidence.

Put together, these reforms show a pattern: clean up the statute book, decriminalise the trivial, modernise labour compliance, strengthen market governance, digitise trade processes, fix logistics, and de-risk long cycle energy investment.

Prime Minister Narendra Modi has consistently argued that the state's job is to reduce the burden on entrepreneurs so that productivity can compound. That is the strategic meaning of Reform Express 2025. The seeds of the next phase of double-digit growth are sown in this quiet, cumulative work, and India is doing it with a steadiness that many economies have lost.

In a quiet and cumulative way, 'Reform Express 2025' is sowing the seeds of the next phase of India's double-digit growth

मुख्य विषय-वस्तु और विश्लेषणात्मक आयाम

1. संस्थागत सुधार और नियामक निश्चितता

- एक प्रमुख बात पूर्वानुमेयता और नियम-आधारित शासन पर ध्यान केंद्रित करना है। अनुपालन में कमी, छोटे अपराधों का गैर-अपराधीकरण, और अप्रचलित कानूनों को निरस्त करना नियंत्रण-उन्मुख विनियमन से सुविधाजनक शासन में परिवर्तन को दर्शाता है।
- यह लेनदेन लागत और नियामक जोखिम को कम करता है, जो भारत में निजी निवेश के लिए प्रमुख बाधा हैं।
- राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली और जिला-स्तरीय सुधार ढांचे भारत की लंबे समय से चली आ रही "अंतिम-मील शासन" समस्या का समाधान करते हुए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों के विकेंद्रीकरण का संकेत देते हैं।

UPSC लिंक: शासन सुधार, नियामक गुणवत्ता, विश्व बैंक के संस्थागत संकेतक, निवेश माहौल।

2. व्यापार नीति: रक्षात्मक से रणनीतिक एकीकरण तक

- भारत के हालिया व्यापार समझौते (यूके, ओमान के साथ और न्यूजीलैंड के साथ वार्ता) अत्यधिक संरक्षणवाद या गैर-आलोचनात्मक उदारीकरण के पहले के चरणों के विपरीत, चयनात्मक और कैलिब्रेटेड व्यापार खुलेपन की ओर एक बदलाव का संकेत देते हैं।
- सेवाओं, कुशल गतिशीलता और बाजार पहुंच पर जोर भारत के तुलनात्मक लाभों को दर्शाता है।
- डिजिटल व्यापार सुविधा उपकरण (ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफॉर्म, टीआईए पोर्टल) सूचना विषमता और प्रक्रियात्मक देरी को संबोधित करके निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाते हैं।

UPSC लिंक: बाहरी क्षेत्र में सुधार, एफटीए, निर्यात-आधारित विकास, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा।

3. स्टार्टअप इकोसिस्टम और डिजिटल मार्केटप्लेस

- स्टार्टअप, ओएनडीसी और जीईएम का विस्तार दर्शाता है कि कैसे राज्य-सक्षम डिजिटल प्लेटफॉर्म विशेष रूप से एमएसएमई के लिए बाजार पहुंच का लोकतंत्रीकरण कर सकते हैं।
- ओएनडीसी प्लेटफॉर्म एकाधिकार को कम करता है और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है।
- जीईएम सार्वजनिक खरीद को एमएसएमई समावेशन के साथ एकीकृत करता है, औपचारिकता और पैमाने का समर्थन करता है।
- महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य: स्टार्टअप्स की स्थिरता, रोजगार की गुणवत्ता और क्षेत्रीय एकाग्रता चुनौतियां बनी हुई हैं।

UPSC लिंक: एमएसएमई, डिजिटल अर्थव्यवस्था, प्लेटफॉर्म गवर्नेंस।

4. श्रम सुधार और रोजगार का औपचारिकीकरण

- चार श्रम संहिताओं का संचालन सबसे परिणामी लेकिन संवेदनशील सुधारों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है।
- 29 कानूनों के समेकन से अनुपालन स्पष्टता में सुधार होता है और इंस्पेक्टर राज कम होता है।
- संभावित लाभों में उच्च श्रम उत्पादकता, बेहतर सामाजिक सुरक्षा कवरेज और बेहतर विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता शामिल हैं।

चिंताएं: राज्य स्तर पर कार्यान्वयन क्षमता और संक्रमण के दौरान श्रमिक अधिकारों की रक्षा करना।

UPSC लिंक: श्रम सुधार, जनसांख्यिकीय लाभांश, विनिर्माण आधारित विकास।

5. रसद और समुद्री सुधार: संरचनात्मक लागत को कम करना

- भारत की लॉजिस्टिक्स लागत (ऐतिहासिक रूप से सकल घरेलू उत्पाद का ~13-14%) एक प्रमुख प्रतिस्पर्धात्मकता बाधा रही है।
- नया समुद्री कानून औपनिवेशिक युग के ढांचे को आधुनिक शासन, विवाद समाधान और सुरक्षा मानदंडों के साथ बदल देता है।
- जहाज निर्माण और समुद्री बुनियादी ढांचे में निवेश रणनीतिक औद्योगिक नीति को दर्शाता है, जिसका उद्देश्य आयात प्रतिस्थापन और मूल्य प्रतिधारण करना है।

UPSC लिंक: बुनियादी ढांचा, रसद दक्षता, औद्योगिक गलियारे।

6. ऊर्जा क्षेत्र में सुधार: दीर्घकालिक विकास प्रवर्तक

- ऊर्जा सुधार लंबे समय तक, पूंजी-गहन निवेश के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
- हाइड्रोकार्बन में संविदात्मक शर्तों की स्थिरता नीतिगत जोखिम को कम करती है।
- अपतटीय अन्वेषण के विस्तार से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ती है।
- एसएमआर सहित परमाणु ऊर्जा सुधार, ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और विश्वसनीयता की त्रिमूर्ति को संबोधित करते हैं।
- विश्लेषणात्मक अंतर्दृष्टि: परमाणु ऊर्जा उन्नत विनिर्माण और डेटा बुनियादी ढांचे के लिए महत्वपूर्ण बेस-लोड पावर प्रदान करके नवीकरणीय ऊर्जा को पूरक करती है।

UPSC लिंक: ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु प्रतिबद्धताएं, कम कार्बन संक्रमण।

7. वित्तीय और बाजार शासन

- प्रस्तावित प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक में खुदरा भागीदारी बढ़ने के बीच पूंजी बाजार के नियमन को आधुनिक बनाने का प्रयास किया गया है।
- मजबूत प्रवर्तन और तेजी से विवाद समाधान निवेशकों के विश्वास को बढ़ाता है।
- घरेलू बचत को उत्पादक निवेश में बदलने के लिए कुशल पूंजी बाजार आवश्यक हैं।

UPSC लिंक: वित्तीय क्षेत्र में सुधार, पूंजी बाजार, निवेश जुटाना।

संश्लेषण: इन सुधारों को क्या महत्वपूर्ण बनाता है?

- संचयी प्रभाव: व्यक्तिगत रूप से विनम्र, सामूहिक रूप से परिवर्तनकारी।
- दूसरी पीढ़ी के सुधार: हेडलाइन उदारीकरण के बजाय कार्यान्वयन, संस्थानों और प्रोत्साहनों पर ध्यान केंद्रित करना।
- जोखिम में कमी: ऊर्जा, व्यापार, श्रम और रसद में, निजी निवेश को जोखिम से मुक्त करने पर जोर दिया जाता है।
- सक्षमकर्ता के रूप में राज्य: प्रत्यक्ष नियंत्रण से पारिस्थितिकी तंत्र निर्माण की ओर बदलाव।

निष्कर्ष

जिन सुधारों पर प्रकाश डाला गया है, वे भारत की विकास रणनीति के एक शांत लेकिन निर्णायक पुनर्मूल्यांकन का प्रतिनिधित्व करते हैं- प्रासंगिक प्रोत्साहन से दूर और संस्थागत लचीलापन और उत्पादकता आधारित विस्तार की ओर। कानून की पुस्तिका को साफ करके, श्रम और बाजार नियमों का आधुनिकीकरण करके, रसद को मजबूत करके और दीर्घकालिक ऊर्जा निवेश हासिल करके, भारत निरंतर उच्च विकास के लिए आधार तैयार कर रहा है। जैसा कि नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया है, राज्य की भूमिका उद्यम का प्रबंधन करने के बजाय घर्षण को कम करने के लिए तेजी से बढ़ रही है। UPSC उम्मीदवारों के लिए, यह एपिसोड दर्शाता है कि कैसे शासन की गुणवत्ता, नियामक निश्चितता और बुनियादी ढांचे की दक्षता एक साथ क्षणिक राजनीतिक आख्यानो से परे आर्थिक परिवर्तन की वास्तविक नींव बनाती है।

UPSC प्रारम्भिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न : राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) को इस प्रकार वर्णित किया गया है:

- A. वाणिज्यिक अदालतों में विवाद समाधान के लिए एक पोर्टल
- B. केंद्रीय और राज्य-स्तरीय व्यापार अनुमोदनों को एकीकृत करने वाला एक डिजिटल प्लेटफॉर्म
- C. सरकारी खरीद तक पहुंचने के लिए एमएसएमई के लिए एक बाज़ार
- D. निर्यात पूर्वानुमान के लिए एक व्यापार खुफिया प्रणाली

उत्तर: B)

UPSC मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न : इस बात पर चर्चा कीजिए कि नियामक निश्चितता और अनुपालन बोझ में कमी भारत में निजी निवेश और दीर्घकालिक आर्थिक विकास में कैसे योगदान करती है। (250 शब्द)

पेज 11 : सामान्य अध्ययन II & III : अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भारतीय अर्थव्यवस्था

हाल ही में संपन्न भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) भारत की विकसित व्यापार कूटनीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। मार्च 2025 में घोषणा के बाद दिसंबर में अंतिम रूप दिया गया, यह समझौता संवेदनशील घरेलू क्षेत्रों की सुरक्षा करते हुए चयनात्मक व्यापार उदारीकरण की दिशा में भारत के कैलिब्रेटेड बदलाव को दर्शाता है। संरक्षणवाद, आपूर्ति-श्रृंखला व्यवधानों और भू-राजनीतिक पुनर्संरखण द्वारा चिह्नित वैश्विक संदर्भ में, एफटीए बाजारों में विविधता लाने, रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में अधिक सार्थक रूप से एकीकृत करने के भारत के प्रयास का उदाहरण है।

EXPLAINER

What is the India-New Zealand Free Trade Agreement?

What zero-duty access will India get, and how much FDI is New Zealand committing to by 2030? Which sectors in New Zealand have criticised the deal? Why is India accelerating FTAs with countries? How will labour-intensive sectors like textiles, leather, gems, and processed foods benefit?

Saeed Pande

The story so far: The recent India-New Zealand Free Trade Agreement (FTA) was concluded in December, under which New Zealand will levy zero duty on 100% of India's exports and bring in \$20 billion in Foreign Direct Investment (FDI) by 2030.

What are the key bargains? India will receive zero-duty market access for all its exports to New Zealand. In return, India will relax tariffs on 95% of imports from New Zealand, with 57% of these products becoming duty-free from day one.

New Zealand has committed to investing \$20 billion in India over the next 15 years, with firm clawback mechanisms in case the investment doesn't meet the stipulated timeline. The FDI is aimed at promoting skill mobility and services, creating employment and growth opportunities across 18 sectors. For the first time, New Zealand has agreed to facilitate trade in Ayurveda, yoga, and traditional medicine services with India.

The deal also makes provisions for the support and mobility of Indian skilled workers. Youth, students, and professionals will find it easier to live and work in New Zealand.

The FTA creates opportunities for India to become a key supplier of skilled workforce in services such as IT professionals, Engineers, Yoga instructors, Indian chefs, Music teachers, as well as in sectors including healthcare, education, and construction.

Student mobility, work permits of up to 20 hours per week while studying, and extended post-study work visa are some of the opportunities for Indian youth to get global exposure.

The agreement also builds on MSMEs and employment opportunities through labour intensive sectors, including textiles and apparel, leather and footwear, gems and jewellery, engineering goods, and processed food items.

Which sectors has India kept outside the agreement?

India has refused to give market access to major items crucial to New Zealand, such as dairy and agricultural products, including milk, cheese, cream, butter, yogurt, onions, sugar, edible oils, spices, and rubber, in order to protect Indian farmers and small and medium industries.

New Zealand will develop focused action plans to develop and improve productivity, quality, and sectoral capabilities for fruit growers in India, particularly for exotic fruits like kiwifruit, apples, and honey. This cooperation will ensure the establishment of centres of excellence, improved planting material, capacity building for growers, technical support for orchard management, post-harvest practices, supply chains, and food safety.

Why is the FTA important?

More than a breakthrough, the India-New Zealand FTA is a framework for deeper cooperation in the future. It is India's conscious move to increase its global economic footprint. Trade diversification demands a deep and deliberate transformation of the country's productive sector and integration into



Strong ties: Prime Minister of New Zealand, Christopher Luxon and Prime Minister Narendra Modi on March 17. SHIV KUMAR PUSHPAKAR

global value chains.

The India-New Zealand FTA is hailed for being the fastest concluded, completed in a record time of nine months after being announced in March 2025. It enhances market access and tariff preferences for Indian exports to New Zealand, while proving to be a gateway to Oceania and Pacific Island markets. Standing at \$49,380, New Zealand is among the higher-income economies in Oceania.

The Indian diaspora in New Zealand constitutes 5% of its population, which amounts to 3,00,000 persons. This creates a promising exchange and opens opportunities for soft power politics between the two nations.

Currently, India's bilateral merchandise trade with New Zealand stands at \$1.3 billion. The deal aims to double this figure over the next five years.

India has instated strict safeguards to protect its sensitive sectors, like agriculture and dairy, from one of the world's largest dairy exporters.

This is also one of the first FTAs negotiated and concluded entirely by a women-led and women-driven team, from the chief negotiating officer to the ambassador to New Zealand.

Why is India accelerating new FTAs?

By engaging with the Pacific, West Asia, and Africa as trade partners, India is leveraging its position and promoting realignments through bilateral engagements and FTAs.

FTAs provide a platform to pursue unique and region-specific commitments, creating room for WTO-plus commitments, especially in areas like services, digital trade, and investment. Diversification of trade partners means that India doesn't have to be dependent on traditional markets such as the EU, the U.S., and China.

FTAs are aligned with India's development goals and policies, such as Make in India, and securing India's sensitive sectors through technology transfers and production-induced incentive schemes that can help in aligning Indian manufacturing with the global value chains.

India is currently determined to materialise FTAs with several countries, including Russia, Oman, the U.K., and New Zealand, in spite of its not-so-successful past FTA engagements. This points to India's attempt at securing strategic and geopolitical alliances via economic and trade liberalisation.

This is India's third FTA this year, after agreements with the U.K. and Oman. It is a part of a broad strategy that India is determined to take forward after the U.S. imposed steep tariffs. A large chunk of India's trade is U.S.-dependent. The bilateral trade between India and the U.S. stands at \$12 billion, and changes in the tariffs by the U.S. really hurt India's trade.

India's exports to the U.S. declined sharply in September and October, dropping to 12% and 8.5%, respectively. The Indo-U.S. free trade deal is in slow progress, and 50% of the tariffs still remain unchanged. This has resulted in a departure from the U.S. and into an urgent need for diversification of India's trade policies and strategic alliances in order to attract greener trade pastures.

One of the main reasons for the stalling of the Indo-U.S. bilateral talks is India's steadfast policy of not opening up its farming and dairy sector to concessions in the FTA. India is thus making a substantial move from short-term economic partnerships to long-term trade alliances.

The India-New Zealand deal builds a structure that is more investor-friendly. India is willing to let go of its protectionist image by lowering trade barriers, promoting ease of business, and opening its markets. India's FTAs today go well beyond tariff reduction; they are more of a framework for future cooperation and economic alignment.

What criticisms does the agreement face?

This is New Zealand's first FTA that excludes dairy and agriculture from its purview, due to which it is heavily criticised in New Zealand by coalition partners of the current government. The Foreign Minister of New Zealand said that the deal is 'neither free nor fair' as it bypasses the dairy and agriculture sector, the country's largest industry, and added that they will vote against the bill when it comes to the floor in the New Zealand Parliament in 2026. India, on the other hand, assumes an easy passage to legislation.

In India, FTAs are criticised for widening trade deficits and generating asymmetric gains, as it has led to imports from partner countries growing faster than our exports. Although the safeguards established by the current India-New Zealand FTA claim to cover these risks and protect and promote India's sensitive sectors through manufacturing collaboration. The success of which will have to be determined as the implementation unfolds over the years.

What is the way forward?

Even though the India-New Zealand FTA is considered historic, it is important to learn from the trade agreements in the past, as many resulted in low yields.

India needs to invest in domestic competitiveness, meet global market standards and quality requirements, ensure strong rules of origin, define anti-dumping provisions, strengthen its sensitive sector and MSMEs and formulate them in line with global markets.

India also needs to invest in research and development for increasing quality and competitiveness of its products if it has to thrive in the global market. Saeed Pande is a freelance writer with a focus on politics, current affairs, international relations, and geopolitics

भारत-न्यूजीलैंड एफटीए की मुख्य विशेषताएं

1. भारतीय निर्यात के लिए शून्य-शुल्क पहुंच

- न्यूजीलैंड को भारत के निर्यात का 100 प्रतिशत शून्य-शुल्क बाजार पहुंच का लाभ उठाएगा, जिससे मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता में काफी वृद्धि होगी।

- यह विशेष रूप से न्यूजीलैंड की उच्च प्रति व्यक्ति आय अर्थव्यवस्था को देखते हुए फायदेमंद है, जो भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के लिए गुणवत्ता के प्रति जागरूक और मूल्य वर्धित बाजार प्रदान करता है।

2. न्यूजीलैंड के लिए बाज़ार पहुंच

- भारत न्यूजीलैंड के 95% निर्यात पर टैरिफ कम करेगा, जिसमें 57% पहले दिन से शुल्क-मुक्त हो जाएगा।
- हालांकि, भारत ने डेयरी और प्रमुख कृषि उत्पादों को स्पष्ट रूप से बाहर रखा है, जिससे छोटे किसानों और एमएसएमई के लिए सुरक्षा सुनिश्चित हुई है।

3. एफडीआई प्रतिबद्धता

- न्यूजीलैंड ने 2030 तक (अगले 15 वर्षों में) 20 बिलियन अमरीकी डालर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) करने की प्रतिबद्धता जताई है।
- विशेष रूप से, समझौते में क्लॉबैक तंत्र शामिल है, जो एफडीआई प्रतिबद्धता को कानूनी और संस्थागत रूप से विश्वसनीय बनाता है - जो भारत के एफटीए अभ्यास में एक नवाचार है।

भारत के लिए क्षेत्रीय लाभ

1. श्रम-गहन क्षेत्र

- एफटीए विशेष रूप से भारत के रोजगार और एमएसएमई उद्देश्यों के साथ जुड़ा हुआ है:
- कपड़ा और परिधान: शून्य-शुल्क पहुंच दक्षिण पूर्व एशियाई निर्यातकों के खिलाफ प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करती है।
- चमड़ा और जूते: प्रीमियम उपभोक्ता आधार से बढ़ी हुई मांग।
- रत्न और आभूषण: उच्च आय वाले बाजार में शुल्क-मुक्त पहुंच मूल्य वर्धित निर्यात को बढ़ावा देती है।
- प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ: ब्रांडेड भारतीय खाद्य उत्पादों के लिए अवसर, "ब्रांड इंडिया" पहल के साथ संरेखित करना।
- ये क्षेत्र भारत की जनसांख्यिकीय लाभांश रणनीति के केंद्र में हैं और इनमें रोजगार की उच्च लोच है।

2. सेवाएं और कौशल गतिशीलता

- न्यूजीलैंड ने आईटी पेशेवरों, इंजीनियरों, स्वास्थ्य कर्मियों, शिक्षकों, योग प्रशिक्षकों, शेफ और संगीत शिक्षकों के लिए रास्ते खोले हैं।
- छात्रों की आवाजाही, अंशकालिक काम (20 घंटे प्रति सप्ताह तक), और अध्ययन के बाद कार्य वीजा के लिए प्रावधान वैश्विक मानव पूंजी आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करते हैं।
- पहली बार, आयुर्वेद, योग और पारंपरिक चिकित्सा सेवाओं को औपचारिक रूप से एफटीए ढांचे में मान्यता दी गई है।

भारत द्वारा बाहर किए गए क्षेत्र: रणनीतिक सुरक्षा

- भारत ने संवेदनशील क्षेत्रों में बाजार पहुंच से इनकार कर दिया है जैसे:
- डेयरी (दूध, पनीर, मक्खन, दही)
- प्रमुख कृषि उत्पाद (प्याज, चीनी, खाद्य तेल, मसाले, रबर)

तर्क:

- लाखों छोटे किसानों की आजीविका की रक्षा करता है
- दुनिया के सबसे बड़े डेयरी निर्यातकों में से एक द्वारा बाजार की बाढ़ को रोकता है
- खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण आय स्थिरता बनाए रखता है
- यह चयनात्मक संरक्षण भारत की पहले के एफटीए से मिली सीख पर प्रकाश डालता है, जहां समय से पहले उदारीकरण के कारण व्यापार घाटा हुआ।

आलोचना और राजनीतिक अर्थव्यवस्था की चिंताएं

न्यूजीलैंड में

- डेयरी और कृषि को बाहर रखने से गठबंधन के सहयोगियों की आलोचना हो रही है।
- न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री ने समझौते को "न तो स्वतंत्र और न ही निष्पक्ष" करार दिया है, जिसमें 2026 में संसदीय अनुसमर्थन के दौरान विरोध का उल्लेख किया गया है।
- यह व्यापार वार्ता में घरेलू राजनीतिक बाधाओं को दर्शाता है, खासकर जब मुख्य निर्यात क्षेत्रों को बाहर रखा जाता है।

भारत में

- आलोचकों का तर्क है कि एफटीए ऐतिहासिक रूप से व्यापार घाटे को बढ़ाते हैं और असममित लाभ उत्पन्न करते हैं।
- हालांकि, इस एफटीए में सुरक्षा उपायों, चरणबद्ध टैरिफ में कटौती और क्षेत्रीय बहिष्करण का उद्देश्य इन जोखिमों को कम करना है।

भारत एफटीए में तेजी क्यों बढ़ा रहा है

व्यापार विविधीकरण

- अमेरिका, यूरोपीय संघ और चीन जैसे पारंपरिक बाजारों पर अत्यधिक निर्भरता को कम करता है।
- अमेरिकी बाजार में टैरिफ झटके और निर्यात में गिरावट के बाद विशेष रूप से महत्वपूर्ण।

विश्व व्यापार संगठन (WTO) से जुड़ी प्रतिबद्धताएं

- एफटीए सेवाओं, डिजिटल व्यापार, निवेश और गतिशीलता में लचीलेपन की अनुमति देते हैं - ऐसे क्षेत्र जहां डब्ल्यूटीओ की प्रगति सीमित है।

रणनीतिक और भू-राजनीतिक संरेखण

- एफटीए दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी के साधन हैं, न कि केवल टैरिफ में कटौती के उपकरण।
- ओशिनिया, पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरेशिया के साथ जुड़ाव भारत की बहु-संरेखण रणनीति को दर्शाता है।

घरेलू सुधार संरेखण

- मेक इन इंडिया, पीएलआई योजनाओं और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण जैसी पहलों का समर्थन करता है।
- संरक्षणवादी इन्सुलेशन के बजाय घरेलू प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है।

अमेरिका के बाद का टैरिफ वातावरण

- भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता में धीमी प्रगति और टैरिफ को बरकरार रखने ने भारत को वैकल्पिक विकास गलियारों की तलाश करने के लिए मजबूर किया है।

भारत-न्यूजीलैंड एफटीए का रणनीतिक महत्व

- ओशिनिया और प्रशांत द्वीप के बाजारों के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है।
- लोगों से लोगों के बीच मजबूत संबंधों का निर्माण करता है, जिसमें भारतीय प्रवासी न्यूजीलैंड की आबादी का ~5% हिस्सा हैं।
- पांच साल में द्विपक्षीय व्यापार को 1.3 अरब डॉलर से दोगुना करने का लक्ष्य।
- यह प्रतीकात्मक रूप से सबसे तेजी से संपन्न एफटीए में से एक और भारत के लिए महिलाओं के नेतृत्व वाली पहली व्यापार वार्ताओं में से एक है।

निष्कर्ष

भारत-न्यूजीलैंड एफटीए भारत की व्यापार नीति में एक गुणात्मक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है – प्रतिक्रियाशील संरक्षणवाद से रणनीतिक, हित-आधारित उदारीकरण की ओर। शून्य-शुल्क पहुंच, विश्वसनीय निवेश प्रतिबद्धताओं, सेवाओं की गतिशीलता और क्षेत्रीय सुरक्षा उपायों को जोड़कर, समझौता घरेलू संवेदनशीलता के साथ विकास की महत्वाकांक्षाओं को संतुलित करता है। हालांकि, इसकी वास्तविक सफलता प्रभावी कार्यान्वयन, घरेलू प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने पर निर्भर करेगी कि एमएसएमई और श्रम-गहन क्षेत्र नए बाजार पहुंच का पूरी तरह से लाभ उठा सकें। भारत के लिए, एफटीए तत्काल व्यापार की मात्रा के बारे में कम है और खुद को लचीले, विविध और भविष्य-उन्मुख वैश्विक आर्थिक नेटवर्क में एम्बेड करने के बारे में अधिक है।

UPSC प्रारम्भिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. न्यूजीलैंड भारत के निर्यात के 100% के लिए शून्य-शुल्क पहुंच प्रदान करने पर सहमत हो गया है।
2. भारत ने न्यूजीलैंड से सभी कृषि और डेयरी उत्पादों के लिए तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान की है।
3. समझौते में क्लॉबैक प्रावधानों के साथ कानूनी रूप से लागू करने योग्य एफडीआई प्रतिबद्धताएं शामिल हैं।
4. आयुर्वेद और योग जैसी पारंपरिक भारतीय ज्ञान प्रणालियों के व्यापार को पहली बार एफटीए में मान्यता दी गई है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है?

- A. केवल 1 और 2 B. केवल 1, 3 और 4 C. केवल 2 और 3 D. 1, 2, 3 और 4

उत्तर: B)

UPSC मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: डेटा-संचालित डिजिटल प्रचार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के सिद्धांतों को कैसे चुनौती देता है? इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए नियामक और तकनीकी उपाय सुझाएं। (250 शब्द)

Invalidate all forms of unilateral talaq

On November 19, 2025, in *Benazeer Heena vs Union of India and Ors.*, a three-judge Bench of the Supreme Court of India comprising Justices Surya Kant, Ujjal Bhuyan and N. Kotiswar Singh, expressed strong reservations about *talaq-e-hasan*, a practice that allows a Muslim man to divorce his wife by pronouncing *talaq* once a month for three consecutive months during *tuhr*, the period of a woman's ritual purity between menstrual cycles. The divorce becomes irrevocable upon the third pronouncement, unless it is withdrawn earlier.

In Heena's case, the husband had communicated the *talaq-e-hasan* through his advocate without signing the document himself. The Court was visibly disturbed by the fact that advocates were granting divorces and remarked: "Tomorrow, what will happen if a client disowns the advocate?... Should a civilized society allow this kind of practice?"

A contract between equals

The concern of the judges was entirely justified, for the *Koran* does not grant men a superior status that entitles them to unilaterally dissolve a marriage either directly or through their agents. This is because, unlike traditions that treat marriage as an indissoluble sacrament, Islam views it as a firm but dissoluble contract between two equals.

The *Koran* uses two legally perceptive terms for marriage – *uqdatan-nikah* (2:235, 2:237), which means the "bond of marriage", and *meesaqaan ghaleean* (4:21), a solemn covenant between a man and a woman that enables them to live together in intimate companionship.

From a contemporary standpoint, these terms parallel the modern prenuptial contract, and thus demand that both spouses be consenting adults acting freely and with full knowledge. The underlying premise is one of equality between



A. Faizur Rahman
is an independent researcher and the Secretary-General of the Chennai-based Islamic Forum for the Promotion of Moderate Thought

two autonomous persons, which negates any hierarchical assumption that places the husband above the wife. For this reason, a unilateral termination of marriage by the husband is impermissible in Islam. Such an act would also contravene the cardinal principle of natural justice, *nemo iudex in causa sua* (that no person may sit in judgment over his own dispute) which Islam upholds.

The Koranic procedure

To guard against deviations from its egalitarian approach, the *Koran* treats divorce extensively in chapters 2, 4, and 65 – *al-Baqara*, *al-Nisa*, and *al-Talaq* – and stipulates four distinct conciliatory measures before the pronouncement of the first *talaq*.

First, it recommends (in 4:34-35) private resolution (*izu hunna*). If this fails, the next step is temporary physical separation (*uhjuru hunna*). Should discord continue, the husband is advised, as a third step, to communicate clearly to his wife (*izribu hunna*) the seriousness of the dispute and attempt to repair the relationship.

For instance, he may tell his wife that unresolved tensions could escalate into public gossip, potentially harming the family. If reconciliation still remains elusive, the *Koran*, as a fourth step, instructs that the issue be brought before two arbiters from the families of both spouses.

Only after all four steps fail is the first *talaq* permitted, followed by *iddah* (2:228-232; 65:1-4). Within *iddah* – three menstrual cycles per 2:228, 229 – no more than two *talaqs* may be issued. For post-menopausal or amenorrhoeic women, *iddah* lasts three months; for pregnant women, it extends until childbirth (65:4).

If reconciliation does not occur during *iddah*, the final irrevocable *talaq* may be issued after *iddah* ends (2:231). Once pronounced, the final

talaq terminates the marital relationship completely.

However, even after the lapse of *iddah*, the *Koran* permits reunion if the final *talaq* has not been invoked: "When you divorce women and they complete their term [*iddah*], do not prevent them from marrying their [former] husbands if they mutually agree on equitable terms" (2:232). In other words, after *iddah*, the couple may either re-contract the marriage on fresh terms or pursue permanent dissolution effected through the third and final *talaq*, declared before two witnesses (65:2).

This is the only *talaq* procedure authorised by the *Koran* and exemplified by the Prophet. It applies to both men and women, consistent with Islam's prohibition of gender-based discrimination. Accordingly, all other modes of divorce, including *talaq-e-bida*, *talaq-e-hasan*, *talaq-e-ahsan*, and *talaq-e-tafweed*, find no support in the *Koran* or the *hadith*.

They originate in *fatawa* traditions crafted by sectarian jurists who, shaped by entrenched patriarchy, rejected women's autonomy and legal personhood. Their stance is starkly reflected in their validation of *talaq-e-hasan*, which permits a husband to dissolve a marriage through an appointed agent (*vakeel*) under the concept of *tawkeel* (agency) – a notion wholly unsupported by *Koranic* or Prophetic precedent and deeply demeaning to women.

An overview

The Supreme Court would thus be on firm constitutional and Islamic footing were it to strike down all unilateral divorce practices available exclusively to Muslim men, retaining only the *Koranic* process, which may be made gender-neutral.

E-mail: themoderates2020@gmail.com Twitter: @FaizEngineer

सामान्य अध्ययन-I : भारतीय समाज और सामाजिक मुद्दे

UPSC मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न : बहुलवादी समाज में ठोस समानता प्राप्त करने के लिए पर्सनल लॉ में सुधार आवश्यक हैं। एकतरफा तलाक और संवैधानिक नैतिकता पर बहस के आलोक में इस कथन पर चर्चा करें। (150 शब्द)

संदर्भ :

बेनज़ीर हीना बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की हालिया टिप्पणियां। (19 नवंबर, 2025) ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत एकतरफा तलाक प्रथाओं पर एक महत्वपूर्ण संवैधानिक और सामाजिक-कानूनी बहस को फिर से खोल दिया है। जबकि तत्काल तीन तलाक (तलाक-ए-बिद) को पहले अपराध घोषित कर दिया गया था, तलाक-ए-हसन के संबंध में अदालत की मजबूत आपत्तियां लिंग-भेदभावपूर्ण तलाक प्रथाओं की अधिक व्यापक जांच की दिशा में एक संभावित

न्यायिक कदम का संकेत देती हैं। यह मुद्दा संवैधानिक नैतिकता, लैंगिक न्याय और बहुवचन कानूनी प्रणाली के भीतर व्यक्तिगत कानूनों के सुधार के चौराहे पर है।

मामले की पेजभूमि

- न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति एन. कोटिस्वर सिंह की तीन सदस्यीय पीठ ने तलाक-ए-हसन की वैधता पर सवाल उठाया, जहां तीन महीने में तीन फैसलों के बाद तलाक अपरिवर्तनीय हो जाता है। न्यायालय विशेष रूप से अधिवक्ताओं के माध्यम से तलाक की प्रथा से परेशान था, जिससे इस बारे में चिंताएँ बढ़ गईं:
- व्यक्तिगत एजेंसी और जवाबदेही का अभाव
- प्रक्रियात्मक निष्पक्षता का उल्लंघन
- विवाह को एकतरफा, छद्म संचालित कार्य में बदलना
- अदालत की टिप्पणी – "क्या एक सभ्य समाज को इस तरह की प्रथा की अनुमति देनी चाहिए?" - इसकी चिंता को दर्शाता है कि इस तरह के तलाक कानून के शासन और महिलाओं की गरिमा दोनों को कमजोर करते हैं।
- इस्लामी न्यायशास्त्र और कुरान की स्थिति

बराबरी के बीच एक अनुबंध के रूप में विवाह

- इस्लाम विवाह को एक संस्कार के रूप में नहीं मानता है, बल्कि दो सहमति और समान व्यक्तियों के बीच एक गंभीर, अघुलनशील अनुबंध (निकाह) के रूप में मानता है। कुरान विवाह का वर्णन इस प्रकार करता है:
- उक्रदातान-निकाह (विवाह का बंधन)
- मीसाकान घलीयन (एक गंभीर वाचा)
- ये शर्तें आपसी सहमति, स्वायत्तता और समानता को रेखांकित करती हैं, पति की किसी भी पदानुक्रमित श्रेष्ठता को खारिज करती हैं। नतीजतन, पति द्वारा विवाह की एकतरफा समाप्ति कुरान की नैतिकता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत दोनों का खंडन करती है (कारण सुआ में निमो iudex)।

तलाक की कुरान प्रक्रिया

- कुरान के अनुसार, तलाक एक अंतिम उपाय है, जिसकी अनुमति केवल एक संरचित, सुलह प्रक्रिया के बाद ही दी जाती है:
- निजी परामर्श और संवाद
- अस्थायी अलगाव
- परिणामों का स्पष्ट संचार
- दोनों परिवारों के प्रतिनिधियों द्वारा मध्यस्थता

इन चरणों के विफल होने के बाद ही पहला तलाक का उच्चारण किया जा सकता है, उसके बाद ईद्दा (एक प्रतीक्षा अवधि) का उच्चारण किया जा सकता है। अंतिम अपरिवर्तनीय तलाक की अनुमति केवल ईद्दा के बाद और गवाहों सहित उचित प्रक्रिया के साथ दी जाती है। महत्वपूर्ण:

- अंतिम तलाक तक सुलह संभव है
- यह प्रक्रिया भावना में लिंग-तटस्थ है, जो समान एजेंसी की अनुमति देती है
- इस प्रकार, कुरान तलाक के केवल एक प्रक्रियात्मक रूप को अधिकृत करता है, तत्काल, प्रत्यायोजित या एजेंट-संचालित प्रथाओं को अस्वीकार करता है।

संवैधानिक आयाम

समानता और गैर-भेदभाव

- मुस्लिम पुरुषों के लिए विशेष रूप से उपलब्ध एकतरफा तलाक प्रथाओं का उल्लंघन होता है:
- अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता)
- अनुच्छेद 15 (लिंग के आधार पर गैर-भेदभाव)
- अनुच्छेद 21 (गरिमा का अधिकार)
- सुप्रीम कोर्ट ने लगातार कहा है कि जब वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो पर्सनल लॉ संवैधानिक जांच से अछूते नहीं हैं।

प्राकृतिक न्याय और कानून का शासन

- तलाक-ए-हसन और कानूनी एजेंटों के माध्यम से तलाक जैसी प्रथाएं कमजोर करती हैं:
- प्रक्रियात्मक निष्पक्षता
- पत्नी की सहमति और भागीदारी
- तलाक देने वाले पक्ष की जवाबदेही
- वे संवैधानिक नैतिकता के विपरीत, प्रभावी रूप से एक पक्ष को अपने स्वयं के कारण में न्यायाधीश होने की अनुमति देते हैं।

कुरान से इतर तलाक प्रथाओं की आलोचना

- तलाक-ए-बिद'ए, तलाक-ए-हसन, तलाक-ए-अहसान और तलाक-ए-तफवीद जैसे रूप:
- कुरान या प्रामाणिक भविष्यद्वाणी अभ्यास में कोई स्पष्ट मंजूरी नहीं है
- पितृसत्तात्मक न्यायिक व्याख्याओं से उभरा
- महिलाओं को कानूनी रूप से अधीनस्थ और तलाक के निष्क्रिय प्राप्तकर्ताओं के रूप में मानें
- उनकी निरंतर मान्यता धार्मिक स्वतंत्रता की आड़ में संरचनात्मक लैंगिक अन्याय को कायम रखती है।

आगे की राह: न्यायिक और विधायी विकल्प

- सभी एकतरफा तलाक प्रथाओं का न्यायिक अमान्य करना पुरुषों तक ही सीमित
- केवल कोरानिक, सुलह प्रक्रिया की मान्यता, लिंग-तटस्थ तरीके से लागू की जाती है
- समानता और गरिमा के संवैधानिक सिद्धांतों के साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ का सामंजस्य
- समुदाय के भीतर से सुधार को प्रोत्साहित करना, पितृसत्तात्मक रीति-रिवाज के बजाय धर्मग्रंथों की प्रामाणिकता पर आधारित

निष्कर्ष

तलाक-ए-हसन पर सुप्रीम कोर्ट की जांच पर्सनल लॉ रिफॉर्म के साथ भारत के चल रहे जुड़ाव में एक निर्णायक क्षण का प्रतिनिधित्व करती है। सभी प्रकार के एकतरफा तलाक को खत्म करना न केवल मजबूत संवैधानिक नींव पर टिका होगा, बल्कि इस्लामी न्यायशास्त्र की समतावादी और न्याय-उन्मुख भावना के साथ भी संरेखित होगा। इस तरह का कदम इस बात की पुष्टि करेगा कि धार्मिक स्वतंत्रता लैंगिक भेदभाव के लिए ढाल नहीं हो सकती है, और संवैधानिक नैतिकता भारत की बहुलवादी कानूनी व्यवस्था का मार्गदर्शक सितारा बनी हुई है।